



04 - लगातार बढ़ी होती
वेधरों की दुनिया



05 - झाबुआ की 'अड़जी-पड़जी'
परंपरा से सुलझाती कृषि की
गुथी

A Daily News Magazine

मोपाल

गुरुवार, 22 जनवरी, 2026



मोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 142, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रु. 2



06 - धार में बसंत पंचमी
उत्सव को लेकर प्रशासन
सतर्क शांति एवं कानून...



07 - विभाग कार्यक्रम की
समस्त तैयारी निधिर्हित
समय सीमा में पूरी...



subahsaverenews@gmail.com



facebook.com/subahsaverenews



www.subahsaverenews



twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

फिर से तपते हुए दिनों की शुरुआत

हवा में अजीब-सी गंध है

और डोमों की चिता

अभी भी दहक रही है

वे कह रहे हैं

एक माह तक मुपत राशन

मृतकों के परिवार को

और लकड़बग्घा हंस रहा है...

और मैं...

फिर से खड़ा हूँ

इस अंधेरी रात की नब्ज को

थामे हुए

कह रहा हूँ

ये तीमारदार नहीं

हत्यारे हैं

और वह आवाज

खाने की मेज पर

बच्चों की नहीं

लकड़बग्घे की हंसी है

सुनो...

यह दहशत तो है

चुनौती भी

लकड़बग्घा हंस रहा है।

- चंद्रकांत देवताले

प्रसंगवश

रजनीश कुमार

यू.एई (संयुक्त अरब अमीरात) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जाएद अल नहयान सोमवार को चंद घंटों के लिए नई दिल्ली आए। इस दौरान ने दिसंबर 2021 में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौर की याद दिला दी, जब वह केवल पाँच घंटे के लिए भारत आए थे। यू.एई और ईरान में भारत के राजदूत रहे केसी सिंह ने द ट्रिब्यून में लिखा कि इस यात्रा की पूर्व सूचना न होना इशारा करता है कि गल्फ और पश्चिम एशिया में तेजी से बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण चीजें सामान्य नहीं हैं। यू.एई के राष्ट्रपति जब दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पहुँचे तो उनकी अगवानी में भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद खड़े थे। पिछले महीने यू.एई के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का भी दौरा किया था। यू.एई के राष्ट्रपति भले नई दिल्ली कुछ घंटों के लिए ही आए लेकिन एक साथ कई समझौते हुए। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चा स्ट्रेटिजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए 'लेटर ऑफ इंटेन्ट' पर दोनों देशों के हस्ताक्षर की हो रही है। दोनों देशों में रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर सहमति तब बनी है, जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले साल सितंबर में एक डिफेंस पैक्ट हुआ था।

यह डिफेंस पैक्ट कहता है कि सऊदी और पाकिस्तान में से किसी एक के खिलाफ 'किसी भी तरह की आक्रामकता' को दोनों के खिलाफ हमला माना जाएगा। यह नेटो के अनुच्छेद-5 जैसा है, जिसका सदस्य तुर्की भी है और जिसकी सेना अमेरिका के बाद सबसे बड़ी है। यू.एई और भारत के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी को लेकर मध्य-पूर्व की न्यूज विश्लेषण

वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई तुर्की ब्यूरो चीफ रेडप सोयलु ने एक्स पर लिखा, "ऐसा प्रतीत होता है कि यू.एई, परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के रक्षा समझौते का संतुलन बनाने के लिए, परमाणु शक्ति संपन्न भारत के साथ साझेदारी कर रहा है।"

सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तलमीज अहमद ने कहा कि यू.एई के राष्ट्रपति का दौरा बहुत ही अहम था। हमारी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप तो पहले से ही थी, लेकिन डिफेंस उस तरह से इसमें शामिल नहीं था। डिफेंस को उस वक्त शामिल किया जा रहा है, जब ईरान और अमेरिका में तनाव है, गाजा का मसला सुलझा नहीं है, सोमानीलैंड को लेकर यू.एई इस्राइल के साथ दिख रहा है, सऊदी और यू.एई में तनाव बढ़ा हुआ है और पाकिस्तान सऊदी के डिफेंस पैक्ट में तुर्की भी शामिल होना चाहता है। ऐसे समय में भारत और यू.एई की द्विपक्षीय रणनीतिक रक्षा साझेदारी को इन पहलुओं से जोड़ना बहुत हरान नहीं करता है। यू.एई के राष्ट्रपति से भारत के प्रधानमंत्री की सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट पर जरूर बात हुई होगी। भारत को कैसे रिएक्ट करना है, इसे भी गंभीरता से सोचना होगा। पाकिस्तान को अचानक से प्रासंगिकता मिल गई है। ऐसे में भारत की रणनीति पश्चिम एशिया में कैसी होगी, यह बड़ा सवाल है."

पिछले साल से तुर्की और सऊदी अरब के संबंध गहरा रहे हैं। मिडिल ईस्ट इस्टीमेट्यूट टर्किश प्रोग्राम की फार्डिंग डायरेक्टर गोनलु तोल मानती हैं कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संबंध, अमीराती नेता मोहम्मद बिन जाएद की तुलना में अधिक मजबूत हैं। इस समीकरण को तुर्की के अधिकारी वॉशिंगटन के साथ

लांबित मुद्दों के समाधान में संभावित रूप से उपयोगी मानते हैं। इन्हीं कारणों से प्रेरित होकर हाल के वर्षों में तुर्की और सऊदी अरब के बीच रक्षा और वित्तीय संबंध गहरे हुए हैं।

यू.एई पश्चिम एशिया में और जीसीसी में अलग नीति पर चल रहा है। यू.एई ने 2020 में इजराइल को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देते हुए राजनयिक संबंध स्थापित किया था। तलमीज अहमद को लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी के डिफेंस पैक्ट की सीमा होगी, क्योंकि इस्राइल भी इसे लेकर बहुत सहज नहीं होगा। यू.एई के राष्ट्रपति के जाने के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि मैं इसे दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद पर्याप्त रक्षा सहयोग का स्वाभाविक विकास मानूंगा, न कि क्षेत्र में घटित किसी विशेष घटना की प्रतिक्रिया के रूप में या बविष्य के किसी काल्पनिक स्थिति में शामिल होने के इरादे के तौर पर।

सऊदी अरब और यू.एई, दोनों ही भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हैं और इसके अलावा बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी कामगार भी इन देशों में रहते हैं। भारत ने अपने महत्वपूर्ण हितों को देखते हुए खाड़ी क्षेत्र में संघर्षों और शत्रुता के मामलों में परंपरागत रूप से सतर्क रह आनाया है।

तलमीज अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की तरह सऊदी अरब से भी भारत के अच्छे संबंध हैं लेकिन पाकिस्तान सऊदी अरब को सुखा की गारंटी देता है और भारत ऐसा नहीं करता है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी मानते हैं कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत और यू.एई के संबंधों में ऐतिहासिक परिवर्तन आया है। यू.एई अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा

व्यापारिक साझेदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, साथ ही वह भारत का एक महत्वपूर्ण ऊर्जा साझेदार भी है। दोनों देशों ने रुपये और दिरहम में व्यापार को सक्षम बनाया है, जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हुई है।

यू.एई में भारत के राजदूत रहे केसी सिंह ने लिखा है, "यू.एई ने बिना टकराव वाली विदेश नीति अपनाई है। खाड़ी और पश्चिम एशिया, अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से और अधिक अस्थिर हो गए हैं और यह भारत के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है।"

दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में असोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सिर क्रमर कहते हैं, "हम पश्चिम एशिया में भारत की हर नीति को पाकिस्तान के आइने में नहीं देख सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच भले डिफेंस पैक्ट पर पिछले साल सितंबर में हस्ताक्षर हुए थे लेकिन दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध दशकों से हैं। पश्चिम एशिया में अभी जो हालात हैं, उनमें यू.एई, इस्राइल और भारत एक साथ दिख रहे हैं। यू.एई और सऊदी अरब का तनाव भी एमबीजेड और एमबीएस के बीच पर्सनल इंगो के कारण है।"

भारत के लिए यू.एई दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है, जहाँ उसी वित्त वर्ष में निर्यात 37 अरब डॉलर तक पहुंच गया। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। यू.एई में 43 लाख से अधिक भारतीय प्रवासी रहते हैं, जो देश की कुल आबादी का लगभग 35 प्रतिशत हैं।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

3 लोगों की दर्दनाक मौत...

- उदयपुर में यात्रियों से भरी जीप खाई में गिरी, 27 लोग थे सवार

उदयपुर (एजेंसी)। राजस्थान के उदयपुर जिले में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। आदिवासी अंचल कोटड़ा में सवारियों से भरी एक जीप अचानक बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, यह जीप बिलवन की ओर से कोटड़ा की तरफ जा रही थी। जैसे ही वाहन चढ़ाई वाले रास्ते पर पहुंचा, अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए। ड्राइवर ने जीप को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण वाहन पर उसका नियंत्रण नहीं रह सका।

7 दशक बाद फिर खोदी गई अश्वमेध यज्ञशाला की जमीन

देहरादून में पुरातत्व विभाग कर रहा चौथी वेदिका की तलाश

देहरादून (एजेंसी)। देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर दूर बाड़वाला स्थित जगतग्राम इन दिनों एक बार फिर इतिहास के पन्नों में लौट रहा है। करीब 7 दशक बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यहां अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी चौथी यज्ञशाला (वेदिका) की खोज के लिए उत्खनन शुरू किया है।

इससे पहले 1952 से 1954 के बीच हुए उत्खनन में तीन यज्ञ शालाएं मिल चुकी थीं, लेकिन चौथी की तलाश अब जाकर दोबारा शुरू हो सकी है। आर्कियोलॉजिस्ट विपुल मिश्रा के मुताबिक, मौजूदा उत्खनन का मकसद तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुए अश्वमेध यज्ञ के दौरान निर्मित चौथी यज्ञशाला को ढूंढना है। चार यज्ञशालाओं में से तीन 1952-54



की खुदाई में मिल चुकी थीं। अब चौथी के लिए फिर से खुदाई की जा रही है।

10 से 14 फीट नीचे तक खुदाई, मिले ब्रिक्स और पांट शेल्टर्स- एक दिसंबर से शुरू हुए उत्खनन में अब तक करीब 10 से 14 फीट गहराई तक खुदाई हो चुकी

है। इस दौरान टीम को प्राचीन ईंटें (ब्रिक्स), मुद्राभांड (पांट शेल्टर्स) और घड़े मिले हैं। विपुल मिश्रा के मुताबिक, मिली ईंटों का साइज और बनाफट ठीक वैसी ही है जैसी 1952-54 की खुदाई में मिली थीं। इससे संकेत मिलता है कि ये उसी काल से जुड़ी हैं।

मध्यप्रदेश ने हरित ऊर्जा को विकास की मुख्य धारा में किया शामिल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रखा मध्यप्रदेश का हरित ऊर्जा विजन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार को दावांस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम-2026 में शामिल होने पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 'डी-रीस्किंग द ग्रीन लोप: सब नेशनल ब्लू प्रिंट फॉर यूटिलिटी स्केल एनर्जी ट्रांजिशन' विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय राउंड टेबल मीटिंग में भागीदारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य की ऊर्जा यात्रा में नवकरणीय ऊर्जा की केंद्रीय भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नवकरणीय ऊर्जा मध्यप्रदेश के समावेशी और टिकाऊ विकास की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को प्रेरणा बताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य स्वच्छ, सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर मध्यप्रदेश ने हरित ऊर्जा को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय सहयोग और बेहतर



समन्वय से राज्य में बिजली और जल आपूर्ति में स्थिरता आई है। इससे आम उपभोक्ताओं के साथ उद्योगों को भी लाभ मिला है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य में सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण से जुड़ी नई नवकरणीय परियोजनाओं की प्रगति और आगामी योजनाओं की जानकारी भी दी।

राउण्ड टेबल मीटिंग के समापन-सत्र में

केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी के हरित ऊर्जा विजन को साझा किया। उन्होंने नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नीति स्थिरता के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वे उपभोक्ताओं और ऊर्जा क्षेत्र के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। केन्द्रीय मंत्री जोशी ने

सुधारोन्मुख राज्यों, विशेषकर मध्यप्रदेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की सौर ऊर्जा संबंधित उपलब्धियाँ वैश्विक स्तर पर साझा की जा सकती हैं। उन्होंने श्रम, भूमि और ऊर्जा के बेहतर समन्वय से स्वच्छ ऊर्जा में जोखिम कम करने के मध्यप्रदेश मॉडल को उल्लेखनीय बताया और प्रौद्योगिकी निवेश और ब्लेंडेड फाइनेंस पर जोर दिया। राउण्ड टेबल मीटिंग में मध्यप्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अशोक खन्ना, अपर मुख्य सचिव नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मनीष सिंह, प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राघवेंद्र कुमार सिंह, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड डॉ. इलैया राजा टी, आयुक्त जनसम्पर्क दीपक कुमार सक्सेना एवं एमडी एमपीआईडीसी चन्द्रमौली शुक्ला उपस्थित रहे।

राजस्थान में कोहरे में 4 गाड़ियां टकराईं, 10 घायल

नई दिल्ली/लखनऊ/जयपुर/देहरादून (एजेंसी)। राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार सुबह धुंध के कारण चार बस-ट्रक को भिड़ंत हो गई। इसके बाद और गाड़ियां बस से टकरा गईं। हादसे में 10 लोग घायल हो गए।

बिहार के अररिया, पूर्णिया सहित 5 जिलों में कोहरा रहा। सुबह विजिबिलिटी कम होने से 5 ट्रेनें लेट चल रही हैं। औरंगाबाद समेत कई शहरों में सुबह से बादल छाप हुए हैं।

मध्य प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को ग्वालियर-रीवा समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट है। इस दौरान कोहरा भी छाया

बिहार में 5 ट्रेनें लेट, उत्तराखंड में चीन बॉर्डर के पास नदियां जमीं

रहेगा। उधर, यूपी सहित देश के 6 राज्यों में दो दिन बाद बारिश की संभावना है। राजस्थान में ओले भी गिर सकते हैं। उत्तरकाशी में चीन सीमा से लगी नेलांग घाटी में नदियां जम गईं। आदि केंलाश (पिथौरागढ़) और केदारनाथ धाम में तापमान -21 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाएं (30-50 किमी/घंटा) भी चल सकती हैं।

मध्यप्रदेश में 23 और 24 जनवरी को बारिश का अलर्ट है। ऐसा स्ट्रॉंग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (पश्चिमी विक्षोभ) की वजह से होगा। ग्वालियर-रीवा समेत 10 जिलों में अस्तर रहेगा। बिहार के गोपालगंज-बगहा में घना कोहरा था। 5 से ज्यादा ट्रेनें लेट थीं, जनवरी लास्ट में फिर बढ़ेगी ठंड। यूपी में आज से 5 दिन बारिश, फिर ठंड बढ़ेगी,कोहरे से लखनऊ में 8 फ्लाइट्स लेट थी। वहीं छत्तीसगढ़ में सर्दी से राहत, न्यूनतम तापमान 14 डिग्री; सीजन के अंतिम पड़ाव में पहुंची ठंड।



दिल्ली में सुनीता विलियम्स बोलीं-

भारत आना घर वापसी जैसा

- चांद पर जाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति मुझे इजाजत नहीं देंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने मंगलवार को कहा, इस समय दुनिया में अंतरिक्ष को लेकर एक तरह की होड़ (सेस रेस) चल रही है। कई देश चाहें और अंतरिक्ष में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ पहले पहुंचना नहीं है, बल्कि यह है कि ईंसान सुरक्षित, टिकाऊ और लंबे समय तक रहने लायक तरीके से चांद पर जाए। सुनीता ने यह बात दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में 'आंखें सितारों पर, पैर जमीं पर' सेमिनार में कही। उन्होंने यह भी कहा कि यह काम सबके फायदे, सहयोग और पारदर्शिता के साथ, लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि किसी एक देश का दबदबा न हो और पूरी मानवता को इसका लाभ मिले।

राममंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्यगोपाल दास की तबीयत बिगड़ी

● 36 घंटे से कुछ भी नहीं खाया, लखनऊ मेदांता रेफर किए गए

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत बिगड़ गई है। 187 साल के नृत्य गोपाल दास को



सोमवार रात से उल्टी-दस्त हो रहे थे। बुधवार सुबह श्रीराम अस्पताल के रिटायर्ड डॉ. एसके पाठक ने उनका चेकअप किया। तुरंत उन्हें लखनऊ मेदांता ले जाने को कहा। जानकारों के मुताबिक, महंत ने पिछले 36 घंटे

से कुछ भी नहीं खाया है। श्रीराम हॉस्पिटल के प्रशासनिक अधिकारी वार्डपी सिंह ने बताया- महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी। डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की।

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नबीन ने पहली नियुक्तियां कीं

● विनोद तावड़े को केरल चुनाव प्रमारी तो शोभा कट्टलाले को सह प्रमारी बनाया



तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने विनोद तावड़े को प्रमारी नियुक्त किया है।

● यूपी विजन डॉक्यूमेंट तैयार, 98 लाख सुझाव आए

● योगी बोले-पंचायतों में भी 30 बैठक की होगी व्यवस्था

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ में सीएम योगी ने कहा- यूपी का विजन डॉक्यूमेंट बनकर तैयार है। 500 जनप्रतिनिधियों के साथ 500 इंटरलेक्टुअल्स ने इसे मिलकर बनाया है। इन लोगों ने ग्रास रूट पर 75 जिलों का सर्वे किया। 98 लाख सुझाव आए और फिर इसे तैयार किया। उन्होंने कहा- विधानसभा में सकारात्मक सोच से काम करेगे तो परिणाम भी आएंगे। संवैधानिक संस्थाएं पारदर्शी और जवाबदेह बनें और इसमें जनभागीदारी भी बढ़े। केवल संसद या विधानसभा को साल में 30 दिन नहीं चलना चाहिए बल्कि यह व्यवस्था पंचायतों में भी लागू होनी चाहिए।

अनूप जलोटा ने रहमान को दी सलाह

● बोले-अगर मुस्लिम होने की वजह से काम नहीं मिल रहा तो हिन्दू बन जाएं



मुंबई (एजेंसी)। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान के काम न मिलने वाले बयान पर सिंगर अनूप जलोटा ने प्रतिक्रिया देते हुए रहमान को सलाह दी है कि अगर उन्हें मुस्लिम होने की वजह से काम नहीं मिल रहा है, तो वे वापस हिंदू बन जाएं।

86वें पीठासीन अधिकारी सम्मलेन में मप्र विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का उद्बोधन विधायकों और लोकतंत्र मजबूत बनाने वाले तत्वों का संरक्षण करे विधायिका: तोमर

लखनऊ/भोपाल। जनता के विश्वास की रक्षा करना हमारा सर्वोच्च दायित्व है। यह विश्वास ही हमारी शक्ति है और यही हमारी जिम्मेदारी भी। विधायिका के सदस्यों का आचरण, सदन के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर, लोकतंत्र की साख से जुड़ा होता है। आज यह आवश्यक है कि हम केवल सिद्धांतों पर चर्चा न करें, बल्कि व्यवहार में भी जवाबदेही को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार करें। जब एक जनप्रतिनिधि जनता के हित की बात करता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। हमें सोचना होगा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले तत्वों का विधायिका कैसे पालन करे और पालन करवाए। हमारी शक्ति विधायकों सहित लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाले तत्वों के संरक्षण में लगनी चाहिए।

यह बात मध्यप्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लखनऊ में आयोजित 86वें पीठासीन अधिकारी सम्मलेन में कही। आयोजन में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला सहित विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, सचिव एवं उत्तरप्रदेश विधानसभा के अधिकारी उपस्थित थे। 'जनता के प्रति विधायिका की जवाबदेही' विषय पर बोलते हुए मप्र विधानसभा के अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायिका के दायित्वों, उनकी चुनौतियों और समाधान पर विस्तृत विचार रखे। श्री तोमर ने कहा कि भारत की शासन व्यवस्था में सत्ता का जनता

के प्रति उत्तरदायी होना वैदिक काल से है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुश्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित 'राम राज्य' वस्तुतः जनोन्मुखी शासन प्रणाली ही है। सम्राट विक्रमादित्य और सम्राट अशोक जैसे कई राजा हुए जिनका शासन जन कल्याण के लिए सदैव उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा संविधान में निहित है और संविधान की जीवनरेखा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन में है। इनमें विधायिका को यह विशिष्ट स्थान प्राप्त है कि वह सीधे जनता के मत से निर्मित होती है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसका जनाधार होता है और उस जनाधार का सबसे सशक्त संवैधानिक मंच विधायिका है। आज के समय में जवाबदेही की परिभाषा और भी व्यापक हो गई है। सूचना का अधिकार, डिजिटल माध्यम, सोशल मीडिया और जागरूक नागरिक समाज ने विधायिका के समक्ष नई चुनौतियाँ और नए अवसर दोनों प्रस्तुत किए हैं। जनता अब केवल चुनाव के समय नहीं, बल्कि निरंतर अपने प्रतिनिधियों के कार्यों पर दृष्टि रखती



है। ऐसे में विधायिका के सदस्यों का आचरण, सदन के भीतर और बाहर दोनों ही स्थानों पर, लोकतंत्र की साख से जुड़ा होता है। गरिमापूर्ण व्यवहार, मर्यादित भाषा और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति सम्मान-ये सभी विधायिका की जवाबदेही के अभिन्न अंग हैं।

सुखना झील को कितना सुखाओगे?

सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की झील को लेकर जताई चिंता

अरावली पर विशेषज्ञ समिति का गठन कानिर्देश



सुखना झील कालगातार गिर रहा जलस्तर

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ की मशहूर सुखना झील के सूखने पर चिंता जताई है। हरियाणा सरकार को पिछली गलतियों को न दोहराने की चेतावनी देते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि अधिकारियों और बिल्डर माफिया की मिलीभगत के कारण सुखना झील पूरी तरह से खराब हो चुकी है। बेंच में सीजेआई सूर्यकांत के अलावा जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी अरावली पहाड़ियों के मामले पर सुनवाई करते हुए की।

अरावली पर विशेषज्ञ समिति के गठन कानिर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अवैध खनन से अपूरणीय क्षति हो सकती है, इसलिए वह अरावली में खनन और संबंधित मुद्दों की व्यापक एवं समग्र जांच के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित करेगा।



सीजेआई सुकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने अतिरिक्त सौलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और न्यायमित्र के. परमेश्वर को चार सप्ताह के भीतर खनन क्षेत्र के विशेषज्ञ पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों के नाम सुझाने का निर्देश दिया, ताकि विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जा सके। बेंच ने कहा कि समिति इस न्यायालय के निर्देशन और निगरानी में कार्य करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस आदेश को भी विस्तारित किया, जिसमें अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की एक समान परिभाषा को स्वीकार करने वाले 20 नवंबर के निर्देशों को स्थगित रखा गया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से बिल्डर माफिया काम कर रहा है। आप सुखना झील को कितना सुखाओगे? आपने झील को तो पूरी तरह से खराब कर दिया है। दरअसल, बारिश के पानी पर निर्भर सुखना झील कभी चंडीगढ़ का प्रमुख पर्यटन केंद्र हुआ करती थी, लेकिन बीते वर्षों में लगातार गिरते जलस्तर ने इसकी सुंदरता और अस्तित्व दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

अविमुक्तेश्वरानंद की चेतावनी- नोटिस वापस लें

प्रयागराज (एजेंसी)। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर स्नान को लेकर प्रशासन और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बीच शुरू हुआ विवाद अब शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच गया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने 24 घंटे में मेला प्रशासन को 8



पेजों का जवाब ई-मेल के जरिए भेजा है। नोटिस को मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, जिससे अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य पद पर बने रहने से रोका गया हो। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए किसी भी तीसरे पक्ष को टिप्पणी करने या रोक लगाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रशासन को नोटिस वापस लेने की चेतावनी भी दी है। कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे।

प्रयागराज में एयरफोर्स का प्लेन क्रैश

शहर के बीचों-बीच हवा में डगमगाया, 2 पायलट को बचाया, माघ मेला से 3 किमी दूर हादसा



उन्होंने बताया, दोनों पायलटों ने सुझबुझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को सुनसान इलाके में उतारा, जिससे आम लोगों की जान-माल को नुकसान नहीं हुआ। हादसे की वजह पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का आदेश दिया गया है। हादसा बुधवार दोपहर 12 बजे



केपी कॉलेज के पीछे हुआ। यह शहर के बीचों-बीच का इलाका है।

एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश दिए

पीआरओ डिफेंस विंग कमांडर देबाथी धर ने बताया- आईएफएफ का माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट बमरोली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी का शिकार हो गया। उसे सुरक्षित रूप से सुनसान इलाके में उतारा गया, जिससे आम लोगों की जान-माल को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं।

हरियाणा-उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को राहुल गांधी की ट्रेनिंग

● कुरुक्षेत्र में इनके परिवारों से भी मिले; सीनियर लीडर्स को एंटी नहीं, अलग कमरे में बैठे



कुरुक्षेत्र (एजेंसी)। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (21 जनवरी) हरियाणा दौर पर थे। सुबह 10:20 बजे अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उनका प्लेन लैंड हुआ था, जहां कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां वे पंजाबी धर्मशाला में चल रहे 'संगठन सृजन अभियान' के ट्रेनिंग कैप में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने सबसे पहले हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिला अध्यक्षों के परिवारों से मुलाकात

की। अब राहुल जिला अध्यक्षों को बंद हॉल में ट्रेनिंग दे रहे थे। सूरों के मुताबिक, ट्रेनिंग में जिला अध्यक्षों के अलावा किसी नेता को नहीं जाने दिया गया। नेता अलग कमरे में बैठे हैं। धर्मशाला में राव नरेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा, सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला समेत विधायक और सांसद भी मौजूद थे।

जिला अध्यक्ष की बेटी बोली-छात्रों की बातें रखी- राहुल गांधी से मुलाकात के बाद चरखों दादरी से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुशील धानक की बेटी जसवीर बॉक्सर ने कहा- मैंने राहुल गांधी से मुलाकात की।

संभल हिंसा

मास्टरमाइंड फरार गैंगस्टर का घर कुर्क

संभल (एजेंसी)। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और कुख्यात फरार गैंगस्टर शारिक उर्फ साठा पर पुलिस का एक्शन जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस उसके घर की कुर्की कर रही है। सुबह 11 बजे से ही 5 थानों नक़्खाशा, रायसती, संभल काँतवाली, हयातनगर और एएचटीयू के 100 से अधिक



पुलिसवाले साठा के घर पहुंचे। नख़ासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला हिंदूपुरा खेड़ा पंजाया में स्थित घर के आसपास पूरे इलाके को छवनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन पहले इलाके में ड्रगड्रग्री बजाकर एक्शन के बारे में अनाउंस किया। फिर साठा के घर पर एक्शन शुरू किया।

गत वर्ष से 8 लाख 22 हजार मीट्रिक टन अधिक हुई धान की खरीदी : राजपूत

इस वर्ष समर्थन मूल्य पर 51 लाख 75 हजार मीट्रिक टन से अधिक हुई धान की खरीदी

भोपाल (नप्र)। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि धान उपार्जन के लिये निर्धारित तिथि 20 जनवरी तक तकत वर्ष से 8 लाख 22 हजार मीट्रिक टन अधिक धान की खरीदी हुई है। इस वर्ष 7 लाख 62 हजार 629 किसानों से 51 लाख 75 हजार 4 मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई है। उन्होंने बताया है कि गत वर्ष 43 लाख 52 हजार 905 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल है। किसानों को अभी तक 9485 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान भी किया जा चुका है।

उल्लेखनीय है कि धान विक्रय के लिये 8 लाख 59 हजार 822 किसानों ने पंजीयन कराया था। एक दिसम्बर से शुरू हुई धान खरीदी के लिये विभिन्न जिलों में 1436 केन्द्र बनाये गये थे। क्रय की गयी धान की 84 प्रतिशत मात्रा 43 लाख 55 हजार 879 मीट्रिक टन का परिवहन किया जा चुका है।

ग्लोबल स्किल पार्क का साउथ कोरिया के प्रतिनिधिमंडल, आईएफएस अधिकारियों एवं विद्यार्थियों ने किया भ्रमण

भारत और साउथ कोरिया के बीच तकनीकी और अकादमिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर हुई चर्चा

भोपाल। साउथ कोरिया के प्रतिनिधिमंडल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बुधवार को संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क का भ्रमण किया। दल ने कौशल विकास, उद्योग से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम को करीब से देखा और समझा।

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, साउथ कोरिया के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत प्रस्तावित वोकेशनल मेकैट्रॉनिक्स प्रयोगशाला की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में साउथ कोरिया गणराज्य का एक उच्चस्तरीय

प्रतिनिधिमंडल बुधवार को ग्लोबल स्किल पार्क पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में श्री चो जियोंग यून, श्री लिम चंकीयो, श्री कांग सुंग बॉग, श्री पार्क चुल सु, श्री किम यंग सैंग, श्री किम मिक यू, श्री किम सुंगयोंग तथा श्री किम मिनसू शामिल रहे। प्रतिनिधियों ने पार्क में स्थापित हाई-टेक प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं, आधुनिक मशीनरी, इंडस्ट्री-ग्रेड प्रशिक्षण सुविधाओं और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप तैयार किए गए पाठ्यक्रमों का अवलोकन किया। इस दौरान भारत और साउथ कोरिया के बीच तकनीकी और अकादमिक सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की गई।

इसी क्रम में आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, भोपाल में आयोजित राज्य

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा (द्वहस्) 2025 बैच के अधिकारियों ने भी ग्लोबल स्किल पार्क का शैक्षणिक एवं औद्योगिक भ्रमण किया। अधिकारियों ने कौशल आधारित शिक्षा मॉडल, उद्योगों की भागीदारी, प्रशिक्षण से रोजगार तक की प्रक्रिया और इंडस्ट्री-रेडी युवाओं के निर्माण की व्यवस्था को समझा और इसकी सराहना की।

इसके साथ ही शासकीय हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के विद्यार्थियों को उच्च शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ने की पहल के तहत सत्र 2025-26 में भोपाल जिले के चयनित विद्यालयों से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 500 से अधिक विद्यार्थियों एवं उनके शिक्षकों ने भी

ग्लोबल स्किल पार्क का भ्रमण किया। कार्यक्रम की शुरुआत ग्लोबल स्किल पार्क के एंथम और प्रेरणादायक वीडियो फिल्मों के प्रदर्शन के साथ की गई।

एक्सपोज़र विजिट के दौरान विद्यार्थियों ने हाई-टेक लैब्स, आधुनिक लाइब्रेरी, इंडस्ट्री-ग्रेड प्रशिक्षण सुविधाओं और अत्याधुनिक अधोसंरचना को नजदीक से देखा। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा, प्रवेश प्रक्रियाओं, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार व करियर से जुड़ी संभावनाओं की व्यावहारिक जानकारी देना रहा, ताकि वे अपने भविष्य को लेकर बेहतर और आत्मविश्वासपूर्ण निर्णय ले सकें।

संपादकीय

ट्रंप का ‘पीस प्लान’ और भारत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति के लिए जो पीस प्लान दिया है, उसका शुरू में भारत समेत कई देशों ने स्वागत किया था, लेकिन जब विस्तार से पूरा प्लान सामने आया है, उससे लगता है कि यह पीस प्लान कम ट्रंप की आर्थिक कूटनीति ज्यादा है। यह पीस प्लान लागू करने के लिए ट्रंप ने एक ‘बोर्ड ऑफ पीस’ के गठन का ऐलान करते हुए दुनिया के करीब 50 देशों को इसमें शामिल होने का ऑफर दिया है, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हैं। भारत को इस बोर्ड में बहुत सोच समझकर शामिल होना चाहिए, क्योंकि इस प्लान के पीछे इरादे बहुत नेक नहीं लगते। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर के मुताबिक ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग़ाज़ा के बोर्ड ऑफ़ पीस में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। बोर्ड गाजा में स्थायी शांति के लिए, स्थायित्व और खुशहाली के लिए वहीं एक अमरदार प्रशासन को सहयोग करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस बोर्ड में शामिल होने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों को न्यौता गया है। पीस ऑफ बोर्ड एक तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी के काम की निगरानी करेगा, जिसे ग़ाज़ा के अस्थायी शासन और उसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इस बोर्ड ऑफ़ पीस में अगर कोई देश शामिल होना चाहता है तो उसे मोटी रकम देनी होगी। यानी बोर्ड के गठन के शुरुआती तीन सालों के बाद भी अगर कोई देश इसमें बने रहना चाहता है, तो उसे एक अरब डॉलर यानी करीब नौ हजार करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। खास बात यह है कि शुरू में तो ट्रंप के इस पीस ऑफ बोर्ड से खुद इजराइल ही खुश नहीं था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वह इस प्लान का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया है। इजराइल की आपत्ति मुख्य रूप से इस प्लान में तुर्की और कतर को शामिल करने को लेकर रही है। लेकिन लगता है कि नेतन्याहू पर ट्रंप का दबाव काम कर गया है। वैसे ट्रंप के इस पीस प्लान को संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है, जिसको लेकर ज्यादातर देश सशक्तित हैं। क्योंकि इससे संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रासंगिकता भी खत्म हो सकती है। एक और अहम बात यह है कि ट्रंप इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष रहेंगे और उन्हीं के पास वीटो पावर भी होगा। यह भी माना जा रहा है कि यह बोर्ड ऑफ पीस न केवल गाजा बल्कि दुनिया में चल रहे विभिन्न संघर्षों को खत्म कर शांति स्थापित करने की पहल है, लेकिन इसके पीछे कितना सात्विक सोच है और कितनी चालबाजी है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। इस बीच अमेरिका का कहना है कि पीस प्लान के इस संस्थापक कार्यकारी बोर्ड का हर सदस्य एक ऐसे विभाग का जिम्मा संभालेगा, जो 'गाजा को स्थिर करने के लिए बेहद अहम' होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कौन किस प्राथमिकता की जिम्मेदारी संभालेगा? फिलहाल इस बोर्ड में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री सर टोनी ब्लेयर, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अमेरिका के मध्य पूर्व के लिए विशेष दूत स्टीव विटक्रॉफ़, ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्लर, अमेरिकी अरबपति मार्क जेवन तथा विश्व बैंक के अध्यक्ष विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा तथा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट गैब्रियेल को शामिल किया गया है। जहां तक भारत की बात है तो संभव है कि वह बोर्ड की तीन साल की अस्थायी सदस्यता स्वीकार कर ले। लेकिन 1 अरब डॉलर देकर स्थायी सदस्यता वह शायद ही ले।

नजरिया

अमित बैजनाथ गर्ग

लेखक पत्रकार हैं।



दुनिया में बेघर लोगों पर रिपोर्ट जारी करने वाली ओईसीडी का कहना है कि सबसे ज्यादा बेघर लोगों वाले देशों की लिस्ट में पाकिस्तान पहले नंबर पर है। वहां करीब 80 लाख से ज्यादा लोग बिना घर के सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। लिस्ट में सीरिया 53 लाख बेघर लोगों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि बांग्लादेश 50 लाख बेघर लोगों के साथ तीसरे नंबर पर है। चीन 25.79 लाख बेघर लोगों के साथ 9वें स्थान पर है। वहीं 25 लाख बेघर लोगों के साथ नेपाल 10वें स्थान पर है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की भी इस लिस्ट में होना यह दिखाता है कि आवास की समस्या एक वैश्विक चुनौती है। वहीं भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा होने के बावजूद बेघर लोगों की संख्या 17.70 लाख तक ही सीमित है।

रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 80 लाख लोगों के बेघर होने की मुख्य वजह देश की आर्थिक अस्थिरता है। पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान गंभीर महंगाई और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही भयानक बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं ने हजारों घर तबाह कर दिए हैं। राजनीतिक अस्थिरता और आवास योजनाओं की कमी के कारण वहां के आम लोगों को छत मुहैया कराना नामुमकिन सा होता जा रहा है। पाकिस्तान में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी भी वहां के लोगों के विकास में बाधा बन रही है। वहां भुखमरी और महंगाई भी चरम पर है, जिसके चलते आम लोगों का जीवन कठिन होता जा रहा है। पाकिस्तान में हालात दुनिया के मुकाबले बहुत विकट हैं, क्योंकि वहां हर तरह की अस्थिरता लोगों की तकलीफों में लगातार इजाफा कर रही है।

अगर भारत की बात करें तो रिपोर्ट कहती है कि 17.70 लाख बेघर लोगों के साथ भारत दुनिया में 13वें स्थान पर है। देश में बेघर लोगों की संख्या कम होने की वजह पीएम आवास योजना का अहम योगदान है। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत करोड़ों परिवारों को अपना घर बनाने में मदद की जा रही है। इससे बेघर लोगों की संख्या में काफी

कमी आई है। इसके अलावा भारत की स्थिर आर्थिक ग्रोथ ने लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ाई है, जिससे उन्हें छोटे-मोटे घर खरीदने में आसानी हुई है। वहीं शहरीकरण और रोजगार बढ़ रहे हैं। बढ़ते शहरीकरण के बावजूद ग्रामीण इलाकों में रोजगार गारंटी जैसी योजनाएं लोगों के पलायन को रोक रही हैं और उन्हें अपने ही गांव में घर बनाए रखने में मदद कर रही हैं। साथ ही मजबूत संयुक्त और पारंपरिक परिवार व्यवस्था भी आर्थिक मुश्किलों के समय लोगों को सहारा दे रही है।

वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने राज्यसभा में



बताया था कि देश में 17.73 लाख लोग बेघर हैं, जिनमें से 9.38 लाख शहरी क्षेत्रों में और 8.34 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। राज्यों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र में 1.80 लाख लोग बेघर हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 1.11 लाख, पश्चिम बंगाल में 1.04 लाख और गुजरात में 84,822 लोग शहरी क्षेत्रों में बेघर हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में 1.48 लाख लोग, राजस्थान में 1.08 लाख लोग, महाराष्ट्र में 99,535 लोग और आंध्र प्रदेश में 69,354 लोग बेघर हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बेघर लोगों की संख्या 3.29 लाख है। इसके बाद महाराष्ट्र में 2.10 लाख, राजस्थान में 1.81 लाख, पश्चिम बंगाल में 1.34 लाख, मध्य प्रदेश में 1.46 लाख, आंध्र प्रदेश में 1.45 लाख और गुजरात में 1.44 लाख लोग बेघर हैं।

अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 24,966 लोग बेघर थे। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली में 46,724 लोग बेघर थे। बेघर लोगों के लिए

काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों का दावा है कि दिल्ली में करीब 1.50 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। इन संगठनों का कहना है कि दिल्ली की तमाम सड़कों, मोहल्लों, फ्लाईओवरों, गुरुद्वारों, बाजारों, रेलवे की खाली पड़ी जमीनों और पार्क-मैदानों में लाखों बेघर लोग रह रहे हैं। इनका दावा है कि दिल्ली का आंकड़ा और भी ज्यादा है, क्योंकि दिल्ली की बेघर आबादी के कई हिस्सों को नहीं गिना जा सका है। मसलन, दिल्ली के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों जैसे पुरानी दिल्ली में देर रात तक काम करने वाले बेघर व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या की गिनती नहीं की जा सकती है।



भारत सहित दुनिया भर में बेघर लोग सड़कों पर, फ्लाईओवर के नीचे या फिर झुमियों में अपने दिन बिता रहे हैं। असल में बेघर लोग समाज के सबसे कमजोर वर्ग में से हैं, जिन्हें लगातार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक गंभीर सामाजिक और मानवीय समस्या बनती जा रही है। बेघर लोगों की स्थिति अत्यंत दयनीय और असुरक्षित होती है, जहां उन्हें भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिससे वे हिंसा, बीमारी (शारीरिक और मानसिक), कुपोषण और अत्यधिक मौसम के संपर्क में रहते हैं और अक्सर सामाजिक कलंक, शोषण और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना करते हैं। किफायती आवास की कमी, गरीबी और नौकरी छूटना मुख्य कारण हैं। कोविड जैसी घटनाओं ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।

बेघर लोगों को हृदय रोग, स्वसन संक्रमण और संक्रामक रोगों का खतरा अधिक होता है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य और आघात की समस्याएं आम हैं। उनकी खराब स्वास्थ्य पैदावों तक पहुंच मुश्किल होती है।

दुनिया के मेले में फंसा शंकराचार्य का रथ

विचार
 ध्रुव शुक्ल
लेखक साहित्यकार हैं।

यह खबर सुनकर आश्चर्य हुआ कि दुनिया के मेले में शंकराचार्य का रथ फंसे गया है। भारी भीड़ के बीच उसकी राह रुकी हुई है। यह कौन-सा रथ है जिसे गज़ा के घाट तक जाने से रोक लिया गया है? शंकर मत से तो हम यही समझते आये हैं कि हमारा शरीर ही रथ है जिसमें इंद्रियों के घोड़े जुते हैं और आत्मा ही उसकी सारथि है। यह शरीर रूपी रथ स्वतः ही गज़ा घाट तक जा सकता है। इसे किसी राज्य व्यवस्था के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। आदि शंकराचार्य तो धर्म स्थापन के लिए अपने शरीर रूपी रथ पर अपने आत्मबल का छत्र तानकर पैदल ही चले।

आठवीं ईस्वी सदी के अंत और नौवीं सदी के प्रारम्भ (788-822) के बीच आदि शंकराचार्य हुए। वे भारत में वेदान्त दर्शन के अद्वैत मत के सर्वनाम्न प्रवर्तक और प्रचारक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मसूत्र पर प्रामाणिक भाष्य भी शंकराचार्य ने ही लिखा। उपनिषदों (ईशावास्य, केन, माण्डूक्य, ऐतरेय, मुण्डक, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, स्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, प्रश्नोपनिषद और कठोपनिषद के भाष्य भी आदि शंकर ने ही किये हैं। श्रीमद्भगवद्गीता पर उनका भाष्य मार्गदर्शी है। शंकराचार्य विरचित विवेक चूडामणि भी प्रसिद्ध है।

आदि शंकराचार्य के समय बौद्ध, जैन और कपालिकों के मतों के प्रभाव में वैदिक धर्म की आभा धुंधली पड़ रही थी तब उन्होंने ब्रह्मसूत्र के भीतम में यह प्रतिपादित किया कि विश्व प्रपंच दृष्टा और दृश्य में बँटा हुआ है। दृष्टा वह है जो दुनिया के मेले में सभी प्रतीतियों का अनुभव करता है और दृश्य वह है जो अनुभव का विषय है। दृष्टा ही साक्षी के रूप में आत्मा कहलाता है और जितने भी दृश्य उसके विषय बनते हैं वे सब अनात्मा है। आत्म निर्विकार है और जीवन के मेले में भटकता विकारग्रस्त अस्थिर अनात्म उस साक्षी आत्मा का स्पर्श नहीं कर पाता क्योंकि आत्म तत्व असङ्ग है। इस आत्म की प्रतीति ही ज्ञान है और भेद से भरे नश्वर अनात्म में चित्त को विकल करना ही अज्ञान है। सर्वोत्तम में अखण्डता का अनुभव करना ही अद्वैत है।

सड़क पर रहने वाले लोग हिंसा, यौन शोषण और चोरी के शिकार होने की अधिक संभावना रखते हैं। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित होते हैं। उन्हें निश्चित और सुरक्षित जगह नहीं मिलती, जिससे वे अत्यधिक ठंड या गर्मी जैसी मौसम की मार झेलते हैं और पानी-स्वच्छता का अभाव होता है। वे अक्सर गरीब, हाशिए पर होते हैं और उन्हें पहचान पत्र या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे वे गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। बेघर होना पर्याप्त आवास के मानवाधिकार का उल्लंघन है और राज्य की सहायता न कर पाने की विफलता को अमानवीय व्यवहार माना जा सकता है।

बेघर लोगों की मदद करने के लिए सबसे पहले तो सरकारों को आगे आना होगा। उन्हें बेघरों को घर बनाकर देने होंगे। किफायती आवास का निर्माण और संरक्षण बेघर होने की समस्या को रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। अधिक आवास इकाइयों का निर्माण आवश्यक है और वर्तमान आवास कम आय वाले परिवारों के लिए सुलभ बने रहने चाहिए। इसके साथ ही आम लोग भी बेघरों की मदद कर सकते हैं। बेघर लोगों को भोजन, कपड़े और स्वच्छता किट देना, आश्रयों में दान या स्वयं सेवा करना और बेघरपन से जुड़े प्रणालीगत मुद्दों के समाधान के लिए वकालत करना शामिल है। साथ ही उन्हें नकदी या उधार काई देना, ताकि वे अपनी जरूरतें खुद चुन सकें। इसके अलावा स्थानीय सरकारी योजनाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। बेघर लोगों से सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और दूसरों को शिक्षित करें कि समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। वहीं स्थानीय बेघर आश्रयों या सहायता समूहों को पैसे, कपड़े या अन्य आवश्यक सामान दान करें। आश्रयों में रसोई में मदद करें, रखरखाव करें या प्रशासनिक कार्यों में हाथ बटाएं। अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क करें और बेघरपन को खत्म करने के लिए प्रणालीगत बदलावों का समर्थन करें। संभव हो तो अपने पुनर्वसन योग्य समान उन लोगों को दें, जो आय के लिए उन्नत पर निर्भर करते हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरतें अलग हो सकती हैं। वहीं स्थानीय सरकारी रैन बसेरों और योजनाओं के बारे में जानकारी रखें और जरूरतमंदों को बताएं। इस तरह हम छोटी व सामान्य मदद करके बेघर लोगों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। हमारा छोटा सा सहयोग उनकी बड़ी जरूरतों को पूरा कर सकता है और हमें यह सहयोग करना ही चाहिए।

ग्रीन लैंड का सपना ट्रम्प का बाल हठ या राज हठ

विश्व राजनीति
 ऋतुपर्ण दवे
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

पुरस्कार न मिलने की खीझ भी स्पष्ट समझ आती है।

रूस और चीन के खतरे की दुहाई देकर ट्रम्प नाटो सदस्य डेनमार्क के ग्रीनलैंड को हथियाने का जो दंभ भर रहे हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों और नाटो की एकता के साथ ही वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा माना जा रहा है। ट्रम्प की जिद कहे या दादागिरी यह उनका दुनिया का तानाशाह बनने जैसा ही कदम कहलाएगा।

देर-सबेर इसका खामियाजा अमेरीका ही भुगतेंगा क्योंकि वैश्विक मंच पर दुनिया का दारगो कहलाने वाले मजबूत देश की विश्वसनीयता बनेगी। ग्रीनलैंड की जिद पर दुनिया भर में शांति के पक्षधर लोगों की समझाइश का भी ट्रम्प पर कोई असर न पड़ना मामले को गंभीर बनाता है। ग्रीनलैंड में 1979 से स्व-शासन है। उसकी विदेश और रक्षा नीति नाटो संगठन का सदस्य देश डेनमार्क देखाता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त भाग है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क सरकारों ने भी हमेशा कहा है कि ग्रीनलैंड न कभी पहले बिकाऊ था न आज है। नाटो देश भी कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दादागिरी कर कब्जा कर ले। खुद यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क और इटली ने भी ट्रम्प के बयान की आलोचना की है। इतना ही नहीं बल्कि सामूहिक तौर पर जवाब देने की बात से भी कह ट्रम्प को चेताया कि हम इसे ट्रॉंसअटलांटिक संबंध भी कमजोर होंगे। ट्रम्प की नीयत तो अपने पहले ही कार्यकाल में ग्रीनलैंड को खरीदने की थी जो तब भी पूरी नहीं हो पाई।

आठ यूरोपीय देशों डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और फिनलैंड पर टैरिफ की

धमकी को ये देश ट्रम्प का ब्लैकमेल, समझ से परे और अनुचित बता रहे हैं। ट्रम्प की हरकतों से यूरोप और अमेरिका के सुरक्षा सहयोग संगठन नाटो के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह दिख रहा है। खुद 80 प्रतिशत अमरीकी भी नहीं चाहते कि ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा बने क्योंकि इससे नाटो में दो फाड़ होंगी जिसका फायदा चीन और रूस जैसे अमेरिका विरोधियों को मिलेगा।

ऐसा भी नहीं है कि यूरोपीय संघ यानी ईयू ट्रम्प के लगाए गए टैरिफ का जवाब देने में पीछे है। ईयू 27 यूरोपीय देशों का राजनीतिक और आर्थिक संगठन है। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन शामिल हैं। इन सभी देशों का रुख अमेरिका पर ट्रेड पारदियाँ लगाने का है जिस पर वो गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जबकि इनका लक्ष्य सदस्य देशों के बीच शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देना है। ऐसी स्थिति में नाटो देश खुद यूरोपीय देश फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, भी अमेरिका की मुखालफत करेंगे। हालांकि ईयू एक खास कानूनी हथियार के इस्तेमाल की सोच रहा है, जिसे ‘ट्रेड बाजूका’ कहते हैं। इसका मकसद उन देशों के खिलाफ कड़ा कदम उठाना है, जो यूरोपीय देशों पर जबरदस्ती आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ईयू सांसद अमेरिका के साथ हुए ट्रेड एग्रीमेंट की मंजूरी रोकने की तैयारी में भी हैं। जाहिर है इससे दो पक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय तनाव बढ़ना ही है जिसमें

अमेरिका के विरोध में कई होंगे। इन सबके लिए जिम्मेदार ट्रम्प ही होंगे।

ट्रम्प की मौजूदा सनक की वजह ग्रीनलैंड है जो सैन्य रणनीतिक लिहाज से बेहद खास है। यह उत्तर अमेरिका और यूरोप के मध्य अटलांटिक महासागर के बीचों-बीच होने से मिड-अटलांटिक क्षेत्र में है। यहां से यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी आसान है। हालांकि यहां अमेरिका का थुले एयर बेस पहले से है, जो मिसाइल चेतावनी और रूसी-चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। आकटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ने से चिंतित अमेरिका ग्रीनलैंड पर वर्चस्व पाकर भू-राजनीतिक पकड़ मजबूत करना चाहता है। दूसरी ओर ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार हैं। ये भविष्य की विशाल आर्थिक और तकनीकी सम्पदा है। अभी चीन का इन उत्पादों पर 70 से 90 प्रतिशत निर्यंत्रण है। यह निरभरता अमेरीका कम करना चाहता है। वहीं भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग के चलते आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नए जलपथ मार्ग खुल रहे हैं। जब ग्रीनलैंड अमेरीका का होगा तो निश्चित तौर पर वह रूस-चीन की बढ़त रोकने में मददगार होगा। इसीलिए ट्रम्प ग्रीनलैंड को अमरीकी सुरक्षा का फ्रन्ट लाइन मानते हैं।

अब ट्रम्प की नीयत चाहे जो वो उनका अंतंरमन ही जाने लेकिन क्या नोबल का शांति पुरस्कार मिलता तो भी ट्रम्प ऐसा करते? अब यह ट्रम्प का बाल हठ है या राज हठ? वहीं जाने फिलहाल ट्रम्प दुनिया में खुद को तमाशा जरूर बना रहे हैं। देखना उनका खेल कब तक चलेगा?

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।
 प्रधान संपादक उमेश त्रिवेदी कार्यकारी प्रधान संपादक अजय बोकिल संपादक (मध्यप्रदेश) विनोद तिवारी वरिष्ठ संपादक पंकज शुक्ला प्रबंध संपादक अरुण पटेल (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा) RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923, Ph. No. 0755-242692, 4059111 Email- subahsaverenews@gmail.com
‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

तथ्य
 सुरेश उपाध्याय
लेखक तथ्यकार हैं।



शाम के वक्त घंटाघर चौहारे पर डोलक की थाप से लोग जूटने लगे थे. गोल घरे के बीच झरू बजाते हुए मदारी ने आवाज लगाई ‘जमूरे, किधर है?’ ‘हाँजिर हैं, उस्ताद’ भीड़ के बीच से प्रकट होते हुए जमूरे ने कहा. कुछ दुनिया-जहाँ की, कुछ इश्वर उधर की बाते करते हुए मदारी ने जमूरे को बीच में दरी पर लेटा दिया व चादर ओढ़ दी. आंगडम बगडम मंत्र उच्चारते हुए मदारी ने सवाल किया ‘जो पूँछूंगा बताएगा’, ‘जी उस्ताद’, जमूरे ने जवाब दिया. इस संवाद के सम्पादित अंश आपके लिए प्रस्तुत हैं -

मदारी - पहली पंक्ति में खड़े नौजवान की तरफ इशारा करते हुए ‘ इस नौजवान का नाम क्या है और इसकी जेब में क्या है?’

जमूरा - विकास नाम के इस युवा की एक जेब फटी है तथा दूसरी कट गई है। (विकास ने दोनों जेब दिखाई और

फटी व कटी जेब देख लोगो ने जोर

पापी पेट का सवाल और उस्ताद-जमूरा संवाद से तालिया बजाई)

- इस युवा का भविष्य क्या है?
- वही जो एक बेरोजगार का होता है.
- धर्म, समाज, साहित्य, खेल आदि आयोगन / संघटन में राजनीतिज्ञ को ही प्रमुख अतिथि / पदाधिकारी क्यों बनाया जाता है?
- राजनीति ही सब क्षेत्र का निर्धारण करती है, अतः राजनीतिज्ञ ही सबसे उपयुक्त अतिथि / पदाधिकारी लगते है.
- अगर दिन लोग भड्काऊ व बेबुनियाद बयान क्यों देते हैं?
- सुविधो में बने रहने के लिए और लोकप्रियता सिद्ध करने के लिए.
- जवन गलतबयानी गले पड़ जाए तो?
- बयानकर्ता का क्या बिगडना है, बयान से बदल जाएंगे, गलत व्याख्या या ए आई का क्रिएशन बता देंगे. वैसे भी माफी और इस्तीफा तो उनके नेता से ही मांगने की परम्परा है. ज्यादा ही हुआ तो खेद व्यक्त कर देंगे.

- रोजमर्रा में नए नवेले नेताओं की क्या तैयारी होना चाहिए?
- माफी मांगो - माफी मांगो का बयान व जलाने के लिए एक पुतला ह्रदम तैयार रखना चाहिए.
- दुनिया में हथियारों की होड़ कैसे रोकी जा सकती है?
- हथियारों के व्यवसाय से ही कई राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था संचालित होती है, अतः इसको रोकने के प्रयास वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं हैं.
- दुनिया में युद्ध क्यों होते हैं तथा उस पर रोक कैसे सम्भव है?
- प्राकृतिक संसाधनों (खासकर कूड़ आईल अर्थात पेट्रोल) व लोकतंत्र जैसी छोटी छोटी आकांक्षा व विश्व का चौधरी बनने की महत्वाकांक्षाओ की पूर्ति के लिए युद्ध होते हैं. हथियार बेचने के लिए भी युद्ध करवाए जाते हैं तथा विश्व चौधरी के फोन व प्रतिबंधो की धमक से रोके जा सकते हैं.
- दुनिया में आणविक, जैविक, रासायनिक आदि घातक हथियारों में सर्वाधिक मारक कौन सा है?
- व्यापार का युग है उस्ताद और सबसे मारक हथियार प्रतिबंध और टैरिफ है.
- संयुक्त राष्ट्र आदि वैश्विक संस्थाओ की विश्व शांति आदि मुद्दे पर क्या भूमिका है?
- जब एक टेलिफोन, कुछ प्रतिबंध और टैरिफ बढ़ाकर ही समस्याओ का निदान हो सकता है तो वैश्विक संस्थाओ की क्या जरूरत है?
- नोबल आदि पुरस्कार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं?
- किसी भी पुरस्कार के लिए अहर्ता व पात्रता निर्धारित होती है, स्वयम भी दावेदारी कर सकते हैं और अपने खास समर्थकों से मांग / अनुशंसा भी करवा सकते हैं.
- क्या किसी को घोषित व प्रदत्त पुरस्कार भी प्राप्त किया जा सकता है?
- पुरस्कार अहस्तांतरणीय होते हैं लेकिन तमो छीने व चुराए जा सकते हैं और प्राप्तकर्ता किन्ही कारणो से दूसरे को तमपा दे देवे तो कोई क्या कर सकता है?

- किसी देश के भूखंड, देश या आइलैंड को किसी भी देश का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है?
- सम्बंधित देश की इच्छा से, क्रय करके या युद्ध में जीतकर एक परम्परागत तरीका रहा है - ‘समरथ्य और शील को ध्वजा-पताकाओं के रां फीके पड़ने मंशा और धमकी न्यू नार्मल है.
- रेअर अर्थ मिनरल्स (दुर्लभ धातु), तख्ता पलट, शासनायक्ष की गिरफ्तारी / अपहरण जैसे थोड़े सवाल और है जमूरे
- बस उस्ताद, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख बहुत लगी है, पापी पेट का सवाल है और हम यह सब उसी के खातिर कर रहे हैं
- ठीक है जमूरे, जनता जनार्दन के सामने फैला दे अपनी झोली, बाबू लोग तुझे निराश नही करेंगे.
- मदारी, झरू बजाते हुए जनता से आख्यान करता है - ‘ साहेबान, मेहरबान, कद्रदान दिल खोल कर रुपये दीएिए और जमूरे की हैसला अफजाई कीजिए, जो दे उसका भी भला और जो न दे उसका भी भला’ भीड़ धीरे-धीरे छंटने लगती है।

खेतों में मौन होता श्रम

निलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकार हैं।



वि रोधाभासों के बीच फंसी खेती भारतीय कृषि आज एक अजीबोगरीब चौराहे पर खड़ी है। अर्थशास्त्री इसे ‘अधिशेष श्रम’ (सरप्लस लेबर) का क्षेत्र कहते हैं, जहाँ आवश्यकता से अधिक लोग नियोजित हैं। लेकिन धरातल की सच्चाई इसके ठीक उलट है। आज गाँव का किसान बुवाई और कटाई के महत्वपूर्ण समय में ‘हाथ’ तलाश रहा है, जबकि खेत में पसीना बहाने वाला मजदूर सम्मानजनक पारिश्रमिक और सुरक्षा के अभाव में शहरों की ओर पलायन कर रहा है। यह केवल एक आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि उस सामाजिक ढांचे का ढहना है जिसने सदियों तक भारतीय गाँवों को आत्मनिर्भर बनाए रखा था। इस गहराते संकट के बीच, मध्य प्रदेश के झाबुआ की आदिवासी परंपरा ‘अड़जी-पड़जी’ एक ऐसी मशाल बनकर उभरती है, जो न केवल श्रम की समस्या का समाधान देती है, बल्कि आधुनिक खेती के लिए एक नया ‘इकोनॉमिक मॉडल’ भी प्रस्तुत करती है।

आज का भारतीय किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खेती में ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ का शोर है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि बुवाई और कटाई के पीक सीजन में किसान को एक मजदूर तक नसीब नहीं होता। जो मजदूर उपलब्ध हैं, उनकी नकद मजदूरी की मांग और किसान की भुगतान करने की घटती क्षमता के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई है।

इस संकट को हल करने के लिए हमने मशीनीकरण और खरपतवारनाशक रसायनों का सहारा लिया। लेकिन इस समाधान ने नई समस्याएं पैदा कर दीं। भारी मशीनों ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बिगाड़ा और रसायनों ने जैव-विविधता को नष्ट किया। सबसे बड़ी मार महिलाओं पर पड़ी, जिनके हाथ से निराई-गुड़ाई जैसे पारंपरिक काम छिन गए। मशीनीकरण ने श्रम की समस्या को हल करने के बजाय उसे ‘विस्थापित’ कर दिया और किसान को कर्ज के नए जाल में धकेल दिया।

अड़जी-पड़जी: सामूहिक श्रम की गौरवशाली परंपरा

जहाँ आधुनिक नीतियां विफल होती हैं, वहाँ आदिवासी समाज का ‘स्थानीय ज्ञान’ मार्ग दिखाता है।

सेहत

डॉ. सत्यकांत त्रिवेदी

वरिष्ठ मनोचिकित्सक, अवसाद, अनिद्रा रोग विशेषज्ञ



हा ल ही में मीडिया में यह खबर पढ़ने को मिली कि रोका के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने यह दावा किया है कि उन्हें पिछले कई दशकों से नींद नहीं आई है। यह समाचार पढ़ते ही स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा होती है, लेकिन उससे भी अधिक एक चिकित्सकीय चिंता पैदा होती है। मैं नींद और मानसिक रोगों का इलाज करने वाला चिकित्सक हूं, इसलिए मुझे लगा कि इस विषय पर चुप रहना ठीक नहीं होगा। ऐसे दावे केवल चौंकाते वाली खबर नहीं होते, बल्कि समाज में नींद को लेकर फैली गलत धारणाओं को भी उजागर करते हैं। एक चिकित्सक के रूप में यह मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस विषय पर सही जानकारी आम लोगों तक पहुंचे।

अस्पतालों में अक्सर कुछ लोग यह कहते हुए मिल जाते हैं कि वे पिछले 20, 30 या 50 वर्षों से सोए ही नहीं हैं। ऐसे कथन को न तो मजाक में लेना चाहिए और न ही बिना जांच के सच मान लेना चाहिए। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो कोई भी व्यक्ति 50 वर्षों तक बिल्कुल नहीं सोया हो, यह जैविक रूप से असंभव है।

नींद मनुष्य की बुनियादी शारीरिक आवश्यकता है, ठीक उसी तरह जैसे भोजन, पानी और सांस लेना। हमारा मस्तिष्क अपने आप यह व्यवस्था करता है कि शरीर को नींद मिले। चाहे व्यक्ति कितनी भी कोशिश

कूटनीति

डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।



सं युक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की शक्ति में अपना ट्रंप-कार्ड यानि तुरूप का पता चल दिया है। बोर्ड ऑफ पीस यानि पीस क्लब को शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने से खफा ट्रंप का अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का उपक्रम माना जा रहा है। उन्होंने पैंसट देशों के राष्ट्राध्यक्षों को इससे जुड़ने का न्यौता भेजा है और इसका सदस्यता शुल्क होगा एक अरब डॉलर। ट्रंप इस क्लब के चेयरमैन हैं और इसकी कार्यकारिणी में उनके दामाद जोरड कुश्नर और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर समेत अनेक राजनयिक और धनसाठे शामिल हैं। गौरतलब है कि यूएसए के दूसरी बार निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वयं को वेनेजुएला का राष्ट्रपति घोषित करने के साथ ही ग्रीनलैंड पर दावा ठेक रखा है और वह कनाडा को अमेरिकी राज्य के तौर पर देखने का सपना पाले हुये हैं।

बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की गाथा गत वर्ष युद्ध जर्जर गाजा में शांति-स्थापना की पहल से होती है। अक्टूबर, सन् 2023 से प्रारंभ युद्ध में इस्रायली कार्रवाई से फलस्तीन को बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा। अगस्त-सितंबर में ट्रंप ने टोनी ब्लेयर के सहयोग से गाजा में आंतरिक प्रशासन और आर्थिक बहाली की योजना प्रस्तुत की। प्रस्ताव को इस्रायल और हमास ने कुबूल कर लिया। 12 अक्टूबर को ब्लेयर फलस्तीन के उपराष्ट्रपति हुसैन अल शेख से जोर्डन में मिले। वार्ता सफल रही और उसी शाम ट्रंप ने गाजा-युद्ध के खात्मे और बोर्ड ऑफ पीस के गठन का

झाबुआ की ‘अड़जी-पड़जी’ परंपरा से सुलझती कृषि की गुत्थी

आज का भारतीय किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ खेती में ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ का शोर है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि बुवाई और कटाई के पीक सीजन में किसान को एक मजदूर तक नसीब नहीं होता। जो मजदूर उपलब्ध हैं, उनकी नकद मजदूरी की मांग और किसान की भुगतान करने की घटती क्षमता के बीच एक गहरी खाई पैदा हो गई है। इस संकट को हल करने के लिए हमने मशीनीकरण और खरपतवारनाशक रसायनों का सहारा लिया। लेकिन इस समाधान ने नई समस्याएं पैदा कर दीं। भारी मशीनों ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बिगाड़ा और रसायनों ने जैव-विविधता को नष्ट किया। सबसे बड़ी मार महिलाओं पर पड़ी, जिनके हाथ से निराई-गुड़ाई जैसे पारंपरिक काम छिन गए। मशीनीकरण ने श्रम की समस्या को हल करने के बजाय उसे ‘विस्थापित’ कर दिया और किसान को कर्ज के नए जाल में धकेल दिया।

झाबुआ और अलीराजपुर के आदिवासी अंचलों में प्रचलित ‘अड़जी-पड़जी’ (Adji-Padji) कोई साधारण प्रथा नहीं, बल्कि श्रम के लोकतंत्रीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है।

‘अड़जी-पड़जी’ का दर्शन सरल और प्रभावी है:

इसमें गाँव के किसान एक-दूसरे के खेतों में सामूहिक रूप से काम करते हैं। यदि आज एक किसान के खेत में बीज रोपना है, तो पूरा गाँव या टोला वहां मौजूद होगा। कल वही समूह दूसरे के खेत में जाएगा। यहाँ श्रम का मूल्य ‘नोटों’ में नहीं, बल्कि ‘सहयोग’ में मापा जाता है। इसमें न कोई मालिक है, न कोई नौकर; हर कोई एक-दूसरे का सहयोगी है।

समाधान के रूप में स्थानीय ज्ञान के लाभ

अड़जी-पड़जी जैसी परंपराएं आधुनिक कृषि की तीन बड़ी चुनौतियों का समाधान करती हैं:

आर्थिक स्वावलंबन: छोटे और सीमांत किसानों के पास नकद राशि का अभाव होता है। अड़जी-पड़जी नकद मजदूरी की आवश्यकता को समाप्त कर देती है, जिससे किसान को साहूकारों या बैंकों से कर्ज नहीं लेना पड़ता।

समयबद्धता और लचीलापन: कृषि में समय का बहुत महत्व है। बारिश होने के साथ ही बुवाई शुरू करनी होती है। अड़जी-पड़जी के माध्यम से जो काम एक

परिवार दस दिन में करता, वह सामूहिक श्रम से एक ही दिन में संपन्न हो जाता है।

श्रम की गरिमा और सुरक्षा: जब किसान एक-दूसरे के खेतों में काम करते हैं, तो काम में ‘सम्मान’ जुड़ जाता है। यह उन मजदूरों के लिए भी एक सुरक्षित विकल्प है जो

आवश्यकता है। एक ‘कृषि श्रम कोष’ (एग्रीकल्चर लेबर फंड) की स्थापना समय की मांग है।

इस कोष का उद्देश्य उन समुदायों और समूहों को वित्तीय प्रोत्साहन देना होना चाहिए जो मशीनीकरण के बजाय पारंपरिक श्रम-साझा प्रणालियों को चुनते हैं। यह



शहरों की असुरक्षित गलियों में धक्के खाने के बजाय अपने समुदाय के बीच रहकर गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं।

कृषि श्रम कोष: परंपरा को नीति का समर्थन

झाबुआ के इस अनुभव को राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए केवल सराहना काफी नहीं है, इसे नीतिगत समर्थन की

कोष छोटे और मध्यम किसानों को संगठित होने, ‘टूल बैंक’ (साझा कृषि उपकरण) बनाने और पीक सीजन के दौरान होने वाले जोखिमों को कवर करने में मदद कर सकता है। यदि सरकार मनेरेगा (MGNREGS) जैसी योजनाओं को इन स्थानीय श्रम-साझा मॉडलों के साथ जोड़ दे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और उत्पादकता दोनों में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है।

50 वर्षों से नींद नहीं आई, क्या यह संभव है?

नींद मनुष्य की बुनियादी शारीरिक आवश्यकता है, ठीक उसी तरह जैसे भोजन, पानी और सांस लेना। हमारा मस्तिष्क अपने आप यह व्यवस्था करता है कि शरीर को नींद मिले। चाहे व्यक्ति कितनी भी कोशिश करे, लंबे समय तक नींद को रोका नहीं जा सकता। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि कोई व्यक्ति कुछ ही दिनों तक लगातार जाग सकता है। इसके बाद भ्रम होने लगता है, चीजें दिखाई देने लगती हैं, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और गंभीर मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए दशकों तक बिना सोए रहना संभव नहीं है।



करे, लंबे समय तक नींद को रोका नहीं जा सकता। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि कोई व्यक्ति कुछ ही दिनों तक लगातार जाग सकता है। इसके बाद भ्रम होने लगता है, चीजें दिखाई देने लगती हैं, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है और गंभीर मानसिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए दशकों तक बिना सोए रहना संभव नहीं है।

तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि उन्हें वर्षों से नींद नहीं आई? इसका कारण वास्तव में नींद का पूरी तरह न होना नहीं, बल्कि नींद को महसूस न कर पाना होता है। कई लोग सोते तो हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे जागते रहे। उनकी नींद हल्की होती है, बार-बार टूटती है और गहरी नींद का अनुभव नहीं हो पाता। इसी कारण उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें नींद आती ही नहीं।

यह समस्या अक्सर अवसाद, चिंता, अत्यधिक बेचैनी, मानसिक उत्तेजना की अवस्थाओं, अन्य मानसिक रोगों या लंबे समय तक नशे के सेवन से

जुड़ी होती है। कुछ मामलों में यह विश्वास इतना मजबूत हो जाता है कि व्यक्ति जांच और समझाने के बाद भी यह मानने को तैयार नहीं होता कि वह सोता है।

चिकित्सकीय दृष्टि से ऐसे मामलों में न तो मरीज की बात को सीधे खारिज किया जाना चाहिए और न ही बिना जांच उसे पूरी तरह सही मान लेना चाहिए। सही तरीका यह है कि नींद से जुड़ी पूरी जानकारी ली जाए, कुछ समय तक नींद का रिकॉर्ड रखा जाए और मानसिक स्थिति का समुचित मूल्यांकन किया जाए।

अंत में यही कहना उचित होगा कि ‘50 वर्षों से नींद नहीं आई’ कोई शारीरिक सच्चाई नहीं, बल्कि एक मानसिक अनुभव है। मरीज को यह समझाना उपचार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि उसका शरीर सो रहा है, लेकिन उसका मन उस नींद को पहचान नहीं पा रहा। जब यह भ्रम धीरे-धीरे दूर होता है, तभी इलाज सही दिशा में आगे बढ़ पाता है।

बोर्ड ऑफ पीस: ट्रंप का नया ‘ट्रंप-कार्ड’

बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की गाथा गत वर्ष युद्ध जर्जर गाजा में शांति-स्थापना की पहल से होती है। अक्टूबर, सन् 2023 से प्रारंभ युद्ध में इस्रायली कार्रवाई से फलस्तीन को बड़े पैमाने पर तबाही का सामना करना पड़ा। अगस्त-सितंबर में ट्रंप ने टोनी ब्लेयर के सहयोग से गाजा में आंतरिक प्रशासन और आर्थिक बहाली की योजना प्रस्तुत की। प्रस्ताव को इस्रायल और हमास ने कुबूल कर लिया। 12 अक्टूबर को ब्लेयर फलस्तीन के उपराष्ट्रपति हुसैन अल शेख से जोर्डन में मिले। वार्ता सफल रही और उसी शाम ट्रंप ने गाजा-युद्ध के खात्मे और बोर्ड ऑफ पीस के गठन का ऐलान कर दिया। गाजा में युद्ध विराम एक बड़ी घटना थी, लिहाजा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव क्रमांक 2803 के जरिये इसका स्वागत किया।



ऐलान कर दिया। गाजा में युद्ध विराम एक बड़ी घटना थी, लिहाजा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव क्रमांक 2803 के जरिये इसका स्वागत किया। जश्न के तौर पर 13 अक्टूबर, 25

को मिस्र में शर्म-अल-शेख में बैठक हुई। इसी क्रम में हमास के प्रवक्ता हाजेम कासिम की शीघ्र टेक्नालाजिकल कमेटी के गठन का बयान सामने आया। ट्रंप का अभियान बाला-बाला चलता रहा

और अंततः 14 जनवरी को ट्रंप ने विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों को बोर्ड ऑफ पीस से जुड़ने का दावतनामा भेज दिया। अगले ही दिन उन्होंने दम्भेवक्ति की कि बोर्ड ऑफ पीस दुनिया में कभी भी और कहीं भी गठित किसी भी संगठन से अधिक प्रतिष्ठापूर्ण उपक्रम है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद होगा संकटग्रस्त इलाकों में शांति स्थापना, धरोसेमंद और वैध-प्रशासन की बहाली तथा स्थायित्व को बढ़ावा। सहज समझा जा सकता है कि ट्रंप संयुक्त राष्ट्र संघ के समांतर एक पृथक् वैश्विक संगठन की इमारत की ईंट चिन रहे हैं। बोर्ड आफ पीस की कार्यकारिणी से इस संभावना को बल मिलता है कि ट्रंप इसे निजी क्लब के तौर पर चलाना चाहते हैं। उनका यह उपक्रम शांति स्थापना से अधिक अपनी ताकत और दबदबा बढ़ाने का हथकंडा अधिक लगता है। तो क्या वे यूएनओ को दरकिनार करना चाहते हैं। उन्होंने चेहरे चुन लिये है। इनमें उनके मित्र है, मंत्री हैं और सलाहकार हैं। वह अकारण नहीं है कि इसे उनके अहंकार या दंभ से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्यपूर्व में यूएनओ के समन्वयक रहे निकोलाई म्लादेनोव इसके डायरेक्टर जनरल होंगे। कार्यकारिणी के अन्य सदस्य हैं अमेरिका के

सेक्रेट्री ऑफ स्टेट माकों रुबियो, मध्यपूर्व में विशेष दूत स्टीव विटकोफ दामाद कुश्नर, ब्रिटन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेअर, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के मार्क रोवान, राजनीतिक सलाहकार रॉबर्ट गैब्रिएल और वर्ल्ड बैंक के भारतीय मूल के अध्यक्ष अजयपाल सिंह बंगाल।

ट्रंप के न्यौते पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने शिरकत की तस्दीक की हैं, वहीं तुर्किये के राष्ट्रपति एर्दोगान की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। अल्बानिया के पीएम एदी रामा ने भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया है और इसे विश्व मंच पर अल्बानिया की बढ़ती प्रतिष्ठा का द्योतक बताया है। अजरबैजान ने जहां इंकार कर दिया है, वहीं फ्रांस के इमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप को ठेगा दिखा दिया है। बड़ी संख्या में मुस्लिम और यहूदी आबादी के अलावा समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व में फ्रांसीसी निष्ठा जग जाछिर है। अमेरिका का स्टेचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस का ही उपहार है। दूसरे योरोपियन यूनियन का हिमायती फ्रांस अमेरिका का पिछ लग्गू नहीं बनना चाहता। मैक्रों के इंकार से शुब्ध ट्रंप का नजला फ्रेंच वाइन और शैंपैन पर गिरा है और उन्होंने इन पर टैरिफ दो सौ फीसद बढ़ा दिया है।

विभाग कार्यक्रम की समस्त तैयारी निर्धारित समय सीमा में पूरी करें: कलेक्टर

गणतंत्र दिवस पर तैयार की जाने वाली प्रदर्शनियां समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने पर्वों, आयोजनों विभागीय योजनाओं सहित अन्य कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए निर्देश

हर ग्राम पंचायत तक पहुंचे संकल्प से समाधान अभियान, गाउँड लेवल अमला भी किया जाए सक्रिय विभागीय योजनाओं, नवाचारों एवं सफलताओं पर केंद्रित हो

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर ने आयोजित समय-सीमा की बैठक में नर्मदा प्रकटोत्सव, चौरागढ़ मेला, तिलक सिंदूर मेला, गणतंत्र दिवस की तैयारियां, संकल्प से समाधान अभियान, धान उपाजन, आनंद उत्सव, सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, समय-सीमा प्रकरण, न्यायालयीन मामलों तथा मुख्य सचिव समीक्षा वीसी के बिंदुओं की विस्तारपूर्वक समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नर्मदा प्रकटोत्सव की सभी तैयारियां समय-पूर्व पूर्ण की जाएं। जल मंच का सौंदर्यकरण, साफ-सफाई, सर्किट हाउस घाट की मरम्मत तथा आयोजन के दौरान होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए।

उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए कि कार्यक्रम की तैयारियां मुख्यमंत्री की संभावित उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तर पर की जाएं तथा हेलीपैड से सर्किट हाउस और जल मंच तक रुट चार्ट चिह्नित किया जाए। ईई पीडब्ल्यूडी को सर्किट हाउस व घाट पर आवश्यक मरम्मत व व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने तथा जिला कमांडेंट होमगार्ड को जल मंच पर पर्याप्त लाइफ जैकेट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

सक्षिप्त समाचार

जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अब 23 जनवरी को होगी

सीहोर (निप्र)। जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक अब 23 जनवरी को दोहरे 12 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। पहले यह बैठक 21 जनवरी को होनी थी, पर 21 जनवरी को कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होने के कारण अब 23 जनवरी को होगी। बैठक में शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, विद्युत मंडल विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, कृषि विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों एवं गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी।

कुपोषित बच्चों की देखभाल एनआरसी में

विदिशा (निप्र)। जिले में कुपोषित बच्चों के बेहतर उपचार एवं पोषण सुधार हेतु संचालित न्यूट्रिशन रीहैबिलिटेशन सेंटर (एनआरसी) में 19 जनवरी को कुल 113 बच्चों को भर्ती किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता लोढ़ा ने बताया कि इन बच्चों को चिकित्सकीय देखरेख में विशेष पोषण आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच एवं आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एनआरसी में भर्ती बच्चों की सेहत में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक एवं पोषण विशेषज्ञों की टीम द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही है। साथ ही बच्चों की माताओं को भी पोषण, स्वच्छता एवं देखभाल संबंधी आवश्यक परामर्श प्रदान किया जा रहा है, जिससे उपचार के बाद भी बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुपोषण मुक्त जिले के लक्ष्य को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और एनआरसी में की जा रही यह भर्ती उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सीएम हेल्पलाइन रैंकिंग में सुधार, समयबद्ध निराकरण से बड़ी प्रशासन की प्रभावशीलता

विदिशा (निप्र)। जिले में सीएम हेल्पलाइन एवं समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध एवं संतोषजनक निराकरण के परिणामस्वरूप रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार दर्ज हो इसके लिए तमाम प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं के निर्देश आज अपर कलेक्टर श्री अनिल कुमार डामोर ने विषयवार विभागों द्वारा लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित पर बल दिया है।प्रशासन द्वारा वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त आवेदनों के साथ-साथ सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे आवेदकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ा है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक आवेदन का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए और समाधान की गुणवत्ता पर विशेष फोकस रखा जाए। अपर कलेक्टर श्री डामोर ने रैंकिंग में गिरावट ना आए इसके लिए टीम वर्क से कार्यों को परिणामक बताते हुए सभी विभागीय अधिकारियों से इसी प्रकार निरंतर प्रयास जारी रखने के निर्देश दिए, ताकि जिले की रैंकिंग और अधिक बेहतर हो सके तथा आमजन को प्रभावी और भरोसेमंद प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त हो सकें।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सीएमएचओ कार्यालय का किया निरीक्षण

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की स्थापना शाखा का अवलोकन किया और वहां संचालित कार्यप्रणाली की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी शासकीय सेवाएं अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन निर्धारित समय-सीमा में सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासकीय कार्यों में अनावश्यक विलंब से आम नागरिकों और हितग्राहियों को परेशानी होती है, इसलिए समयबद्धता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हितग्राहियों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए विभागीय समन्वय और कार्य की नियमित समीक्षा की जाए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने रिकॉर्ड संधारण, फाइलों के समय पर निराकरण तथा कर्मचारियों की उपस्थिति पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए।



एडीएम श्री राजीव रंजन पांडे को कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए। बैठक में कलेक्टर ने चौरागढ़ मेले की तैयारियों की समीक्षा करते हुए एसडीएम पिपरिया को निर्देशित किया कि पार्किंग व दुकानों की नोलामी हेतु विधिवत निविदाएं आमंत्रित कर आगे की कार्रवाई करें। महाशिवरात्रि के अवसर पर तिलक सिंदूर मंदिर में लगने वाले मेले को लेकर कलेक्टर सुश्री मीना ने एसडीएम इटारसी को मंदिर पहुंच मार्ग व सीड़ियों की मरम्मत पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही मंदिर समिति के साथ बैठक कर समन्वयपूर्वक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी

निर्देशित किया गया। उन्होंने 26 जनवरी को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, झांकियों को तैयार किए जाने के लिए भी विषयवार निर्देश दिए।

कलेक्टर ने निर्देश दिए की गणतंत्र दिवस समारोह के लिए विभागों द्वारा तैयार की जाने वाली झांकियां केवल औपचारिकता मात्र ना हो अपितु विभागीय योजनाओं नवाचारों, सफलता की कहानियों पर केंद्रित हो। उन्होंने कहा कि सभी विभाग अव्वल स्थान प्राप्त करने के उद्देश्य से ही झांकियां तैयार करें। कलेक्टर ने संकल्प से समाधान

अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले शिविरों में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करने तथा आवेदनों का समय-सीमा में निपटारा सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने समस्त एसडीएम को नियमित रूप से शिविरों के आयोजन तथा शिविरों के माध्यम से अधिकाधिक आवेदनों को दर्ज कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों का पोर्टल पर अद्यतन अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि अभियान की प्रगति पारदर्शी एवं प्रभावी रहे।

उन्होंने अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों की योजनावार समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि ग्राउंड लेवल अमले को पूरी तरह सक्रिय किया जाए तथा अभियान का क्रियान्वयन प्रत्येक नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर पर सुनिश्चित हो। कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान अवधि में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। साथ ही उन्होंने आगामी दो दिवसों में अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त करने के निर्देश भी दिए।समय सीमा की बैठक के दौरान जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि जिले में संचालित धान खरीदी के तहत अब तक लगभग 22183 किसानों ने 259660 मेट्रिक टन स्कंध का उपाजन किया गया है। जिसमें से 252523 मेट्रिक टन स्कंध का सफल परिवहन किया जा चुका है तथा 560.74 करोड़ रुपये के ईपीओ जनरेट किए जा चुके हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए की शेष रेडी ट्रांसपोर्ट धान का परिवहन कर शेष किसानों को

भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने आनंद उत्सव की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की सभी सीईओ एवं सीएमओ पोर्टल पर आवश्यक रूप से पंजीजन करें। उन्होंने निर्देश दिए की सभी एसडीएम आनंद उत्सव के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का, आयोजन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सुनिश्चित करें साथ ही संकल्प से समाधान अभियान की बैठक जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में कर अभियान की रूपरेखा से सभी को अवगत कराएं।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आनंद उत्सव के तहत किया जा रहे कार्यक्रमों में पत्रकार बंधुओं की भी उपस्थित दर्ज करवाई जाए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के तहत लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए रायचव्य, वन, श्रम, एलडीएम आदि विभागों के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि सभी अधिकारी शिकायतों के समाधान में अपेक्षित प्रगति दर्ज करें। इसी प्रकार कलेक्टर ने समय सीमा के लंबित मामलों के निराकरण में भी गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनसुनवाई के लंबित मामलों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया की पुरानी शिकायतों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए एक सप्ताह के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रभारी अधिकारी जनसुनवाई को पूर्व में जारी किए गए नोटिस के जवाब तथा निराकृत आवेदनों की विस्तार पूर्वक जानकारी बनाकर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, एडीएम श्री राजीव रंजन पाण्डे, अपर कलेक्टर श्री अनिल जैन, श्री बृजेंद्र रावत सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

परम्परागत खेती की जगह उन्नत तकनीक से खेती कर युवा किसान धीरज ने बदली अपनी तकदीर

क्षेत्र में किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनें युवा किसान धीरज



ढेड़ एकड़ हिस्से में 'ताड़वान पिक' किस्म के अमरुद और एक एकड़ में सब्जी टमाटर, गोभी, मेषी, भिंडी आदि की आधुनिक खेती शुरू की। उन्नत किस्म के पौधों और सटीक प्रबंधन के कारण उन्हें उम्मीद से बेहतर गुणवत्ता और पैदावार प्राप्त हुई।

'आत्मा' परियोजना बनी सफलता की आधारशिला : धीरज की इस सफलता के पीछे कृषि विभाग की 'आत्मा' परियोजना का बड़ा योगदान है। परियोजना के विशेषज्ञों ने धीरज को मिट्टी परीक्षण से लेकर कीट प्रबंधन और आधुनिक सिंचाई पद्धतियों की बारीकियों से अवगत कराया। कृषि विभाग के निरंतर

मार्गदर्शन ने धीरज के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उन्हें जोखिम लेने की शक्ति दी। धीरज की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने जिला कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा की पहल पर जिले में शुरू किए गए 'जैविक हट' में अपने उत्पाद बेचना शुरू किया। यहाँ उन्हें बाजार के बिचौलियों से मुक्ति मिली और अपने शुद्ध, जैविक उत्पादों का सीधा लाभ मिला। स्थानीय ग्राहकों द्वारा उनके ताड़वान पिक अमरुद को हाथों-हाथ लिया गया, जिससे धीरज को सामान्य बाजार की तुलना में कहीं अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। अपनी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए युवा किसान धीरज सुरमा कहते हैं कि खेती में अब अपार संभावनाएँ हैं। बस जरूरत है सही जानकारी और आधुनिक तकनीक को अपनाने की। वह जिला प्रशासन और आत्मा परियोजना के आभारी हैं, जिन्होंने उन जैसे छोटे किसान को बाजार और तकनीक से जोड़कर सशक्त बनाया। युवा किसान धीरज की सफलता क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है, जो यह साबित करती है कि खेती यदि सुझबूझ से की जाए, तो यह किसी भी बड़े व्यवसाय से कम नहीं।



कमिश्नर ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की आंगनबाड़ी केन्द्रों का किया भ्रमण

नर्मदापुरम (निप्र)। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने नर्मदापुरम जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्रों का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन के हिसाब से मिलने वाले पोषण आहार भोजन एवं नाश्ते का अवलोकन किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों ने कमिश्नर श्री तिवारी को कविताएं भी सुनाई। कमिश्नर पुलिस लाइन स्थित शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी केन्द्र पहुंचे यहां उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया। आंगनवाड़ी सहायिका शकुन लोवशी ने बताया कि 03 से 06 वर्ष के 34 बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज हैं, जिनमें से कुछ बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं इस कारण से आंगनबाड़ी केन्द्र में नहीं आते हैं। मौके पर छह बच्चे मौजूद थे। कमिश्नर ने प्रातः मिलने वाले

नाश्ते की जानकारी ली, आंगनवाड़ी सहायिका ने बताया कि नाश्ते में बच्चों को आज पौष्टिक खिचड़ी दी गई है। कमिश्नर ने शहरी क्षेत्र के आंगनबाड़ी केन्द्र क्रमांक 41 पहुंचे, आंगनवाड़ी कार्यक्रमता दीपिका सिरोटिया ने बताया कि 03 वर्ष से 06वर्ष तक की आयु के 31 बच्चे आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज हैं जिनमें से 22 बच्चों ने स्कूल में प्रवेश लिया है। शेष बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं। कमिश्नर तत्पश्चात ग्राम ब्यावरा की ग्रामीण क्षेत्र की आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक 04 पहुंचे। आंगनवाड़ी सहायिका श्रीमती प्रीति बकोरे ने बताया कि 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के 07 बच्चे आज उपस्थित है वहीं 3 वर्ष से 6 वर्ष के 29 बच्चे आंगनबाड़ी में दर्ज है जिनमें से 10 से 12 बच्चे आंगनबाड़ी आते हैं शेष बच्चों ने स्कूल में प्रवेश ले लिया है वह स्कूलों में जाते हैं।

ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश कार्यक्रम में स्वदेशी अपनाने और स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण का संदेश

राष्ट्रीय युवा दिवस पर ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश का सेक्टर कार्यक्रम हुआ



विदिशा (निप्र)। जन अभियान परिषद विदिशा द्वारा ग्रामोदय से अभ्युदय मध्यप्रदेश अंतर्गत जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत ग्रामों में भी स्वदेशी अपनाने और स्वच्छता व पर्यावरण संरक्षण के संदेशों का संप्रेषण किया जा रहा है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जन अभियान परिषद, बासीदा द्वारा ग्राम विकास पखवाड़ा के तहत सेक्टर स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन परिषद द्वारा चयनित नवांकुर संस्था आवरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के तत्वाधान में ग्राम विकास प्रस्पुटन समिति कुल्हार के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम अंतर्गत ग्रामोदय

से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के तहत स्वामी विवेकानंद व्याख्यान माला एवं युवा दिवस विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद जी एवं मां सरस्वती जी के चित्र के समक्ष पूजन-अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर आवरण सोशल वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष श्री अमित शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए ग्रामीणजनों को स्वदेशी अपनाने, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को ग्राम विकास की आधारशिला बताया। ग्राम के शासकीय माध्यमिक विद्यालय के

प्रभारी शिक्षक श्री नेतराम विश्वकर्मा ने कहा कि किसी भी कार्य को परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए तथा जीवन में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं ग्राम के उपसरपंच श्री राधेलाल अहिरवार ने गांव में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग से श्री अनिल खरे ने बच्चों के टीकाकरण एवं महिलाओं के संतुलित खान-पान के महत्व पर जानकारी दी।

कार्यक्रम में एमएसडब्ल्यू के छत्र मोनू विश्वकर्मा ने गीत के माध्यम से प्राचीन भारत एवं विक्सित भारत की संकल्पना प्रस्तुत की , जबकि छात्रा वैशाली अहिरवार ने देशभक्ति गीत से उपस्थित जनसमूह को भावविभोर किया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर सभी उपस्थित जनों को स्वदेशी अपनाने की शपथ दिलाई गई तथा ग्राम में रैली के माध्यम से जन-जागरूकता फैलाई गई। साथ ही गांव की दीवारों पर प्स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ जैसे नारों का लेखन भी किया गया।कार्यक्रम का संचालन परामर्शदाता श्री जगदीश साहू द्वारा किया गया एवं आभार प्रदर्शन श्रीमती सीमा शर्मा ने किया। कार्यक्रम में गौरव शर्मा, प्रस्पुटन समिति किशनोदा से चंद्रभान दांगी, कुल्हार शर्मा से थान सिंह दांगी, उदयपुर समिति से सुंदर शर्मा, बावली समिति से राहुल यादव, गोलू अहिरवार, शिक्षक नारायण प्रसाद शर्मा, कसान शांक्व, उपसरपंच करेलाल अहिरवार, आशा सुपरवाइजर विदेश मिश्रा, आशा एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्रामवासी एवं बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

संकल्प से समाधान अभियान का हो प्रभावी क्रियान्वयन, नागरिकों को मिले लाभ: कलेक्टर

कुपोषणमुक्त जिला बनाने कार्या में तेजी लाने दिए निर्देश टीएल बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने की सीएम हेल्पलाईन और विभागीय गतिविधियों की समीक्षा



जानकारी ली। उन्होंने स्वास्थ्य तथा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को लेकर शुरू में बेहतर काम हुआ है, लेकिन अब गति धीमी हो गई है।

अधिकारी इसको गंभीरता से लें तथा कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने जनसहयोग, समाजसेवी एवं विभिन्न संगठनों के सहयोग से कुपोषित बच्चों को फूड बॉस्केट वितरण कार्य में तेजी लाने और

मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों की जानकारी लेते हुए परीक्षा परिणामों में वृद्धि हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। साथ ही जिला अधिकारियों को उन्हें आवंटित शासकीय स्कूलों का निरीक्षण कर बच्चों से संवाद कर उन्हें मोटिवेट करने के लिए निर्देशित किया।

इसी प्रकार सभी एसडीएम से एसडीएम तथा तहसील कार्यालयों को आईएसओ सर्टिफाइड कराने की जा रही कार्यवाही की जानकारी लेते हुए सभी अधिकारियों को अपने कार्यालयों को व्यवस्थित करने तथा दस्तावेजीकरण हेतु दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने विभागवार सीएम हेल्पलाईन शिकायतों और उनके निराकरण की साप्ताहिक प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाईन शिकायतों का समयवधि में संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा करते हुए विगत एक सप्ताह में लंबित 226 सीएम हेल्पलाईन शिकायतों में से 84 का निराकरण करने पर सीएमएचओ डॉ दिनेश खत्री की सराहना करते हुए उन्हें शेष लंबित 142 शिकायतों को भी शीघ्र निराकृत करने हेतु निर्देशित किया।

किया। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग की लंबित 162 सीएम हेल्पलाईन में से 50 शिकायतों का निराकरण होने पर जिला शिक्षा अधिकारी की भी सराहना करते हुए शेष लंबित शिकायतों को भी शीघ्र निराकृत कराने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला बाल विकास, लोक निर्माण विभाग, सामाजिक न्याय, सहकारिता, मत्स्य पालन, उद्यानिकी सहित अन्य विभागों की सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा कर दिशा-निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री विश्वकर्मा ने नॉन अटेन्डेंट सीएम हेल्पलाईन शिकायतों की समीक्षा के दौरान कृषि विभाग, मार्केटंड, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पीएमजीएसवाय तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सीएम हेल्पलाईन शिकायत नॉन अटेन्डेंट रहने पर नाराजगी जाहिर कर संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने हेतु निर्देशित किया।

